देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में रामदेवरा से भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कांग्रेस, राहुल गाँधी और राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया। जनसभा में, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी.पी. जोशी सहित भाजपा के अनेक नेता उपस्थित थे।

'20 साल से राहुल यान की ना लॉन्चिंग हो पाई ना लैंडिंग'

राजनाथ सिंह ने रामदेवरा में आयोजित जनसभा में यह भी कहा कि, ट्रांसपरैंसी इंटरनैशनल की रिपोर्ट में राजस्थान भ्रष्टाचार में नम्बर वन है

- **कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी मौजूद थे।**
- **केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामदेवरा में भाजपा की तीसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जनसभा को संबोधित किया।**

पोकरण/रामदेवरा, 4 सितम्बर (निसं)। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में सोमवार को भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज़ हुआ। इस अवसर पर आयोजित आम सभा में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, भारत के चंद्रयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग तो सफलतापूर्वक हो गई, लेकिन राहुल यान की 20 साल से न तो लॉन्चिंग हुई ना ही लैंडिंग हो पाई। राजस्थान के बारे में उन्होंने कहा कि, ट्रांसपरैंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर एक पर है।

उन्होंने कहा, राजस्थान में अशोक गहलोत के कार्यकाल में पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। मु.मंत्री गहलोत जिस गाडी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं उसका क्लच और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। राजस्थान अपराध की दृष्टि में सबसे अग्रणी श्रेणी में आ रहा है।

राजनाथ सिंह ने तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित करते हुए बताया कि, यह यात्रा जोधपुर संभाग में 20 दिन में 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए 28 दल एक साथ गठबंधन कर सनातन धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस चुप है, राहुल प्रियंका सहित कांग्रेस के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि, भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2027 तक टॉप 3 में होगा, 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी। अब 9 साल बाद भारत पांचवें स्थान पर आ गया है।

पोकरण के बारे में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, परमाणु नगरी में पांच-पांच परमाणु परीक्षण किए गए हैं। यह भूमि गौरव बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा, भारत चांद पर तो पहुंच गया, अब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर हम आदित्य से सूर्य की तरफ जा रहे हैं। हॉलीवुड फिल्मों से भी कम बजट में यह काम हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। भारत अब कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर देशों में है।

राजनाथ सिंह ने राजस्थान की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, राजस्थान में अपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान जैसे हालात कहीं नहीं हैं। दुष्कर्म व छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं। जोधपुर में पूरे परिवार की हत्या हुई और उदयपुर में जो हुआ वह भी सभी को याद है। यह यात्रा परिवर्तन का शंखनाद है। कांग्रेस और भाजपा के शासन का लोग खुद आकलन कर रहे हैं।

आम सभा को संबोधित करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की ख्याति पूरे विश्व में जमाई है, देश में गरीबी कम की है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।

राम मंदिर निर्माण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस ने झांसा देकर सरकार बनाई, उंगलियों पर गिनकर 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कही, लेकिन किया नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है।

इस अवसर पर भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उदबोधन में कहा कि, कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती है।

कभी रामसेतु के अस्तित्व को नकारती है, कभी राम मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक बनाया।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने अपने उदबोधन में कहा कि, राजस्थान सरकार ने "लूट सके, तो लूट ले" वाली कहावत पर चलकर भ्रष्टाचार का तांडव मचाया हुआ है। युवाओं के सपने रोकने का काम करते हुए किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है।

राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, यह क्षेत्र वतन परस्तों की ज़मीन है, यहाँ एक परिवार का कब्जा है। सालेह मोहम्मद मंत्री हैं, एक भाई प्रधान, एक प्रमुख है। इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि, कांग्रेस भ्रम फैलाती है कि भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। भाजपा ने कभी आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी ने कहा कि, देश अग्रणी पथ पर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र का चौमुखी विकास करने के लिए आगामी 2023 व 2024 चुनाव में न झुकेंगे, न दबेंगे, न प्रलोभन में आएंगे, क्षेत्र की जनता समझ चुकी है।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा युवा नेता आईदान सिंह भाटी, प्रियंका मेघवाल, मदन सिंह राजमथाई, अनंत राम बिश्नोई, छोटू सिंह भाटी, जितेंद्र सिंह भाटी सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे।

केन्द्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट

- **आदर्श नगर ब्लॉक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा के सामने विधायक रफीक खान व एक अन्य दावेदार इलियास कुरैशी के समर्थक आपस में लड़ पड़े।**
- **टिकट के अन्य दावेदारों ने मंच पर विधायक रफीक खान की फोटो लगाने पर आपत्ति की और कहा कि, संगठन की बैठक में विधायक की फोटो क्यों, बस इसी मुद्दे पर बहस शुरू हुई जो मारपीट में बदल गई।**

जयपुर, 4 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस के टिकट वितरण से पहले ही कई जिलों से जूतम पैजार की खबरें आ रही थीं। अब जयपुर में एक विधानसभा क्षेत्र में हुई बैठक में पर्यवेक्षक के सामने ही दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया जिसमें एक दावेदार को दो बार पीटा गया और दो बार थाने में एफ.आई.आर. लिखवानी पड़ी।

जयपुर की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा सोमवार को राजधानी जयपुर के आदर्श नगर ब्लॉक की बैठक लेने आई थीं।

इस दौरान विधायक रफीक खान के समर्थकों और अन्य दावेदारों के बीच जबरदस्त हंगामा हो गया। दावेदार इलियास कुरैशी ने कहा कि, जब संगठन की बैठक हो रही है तो मंच पर विधायक का फोटो क्यों लगा है। वहीं, उन्होंने मांग उठाई कि कुरैशी समाज को कांग्रेस कुछ नहीं देती है, इसलिए इस बार कुरैशी समाज को टिकट दिया जाए। अन्य दावेदारों ने भी विधायक रफीक खान का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि यह हंगामा और मारपीट शुरु हो गई। इसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। इस दौरान रफीक खान समर्थकों ने एक दावेदार, एडवोकेट अफजल के साथ मारपीट की जिससे उसका दांत टूट गया और इसके बाद एडवोकेट अफजल ने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर मेडिकल होने के बाद अफजल जिला कांग्रेस अध्यक्ष, आर.आर. तिवारी और पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा को पूरा घटनाक्रम बताने आए और सब कुछ बताकर जब जा रहे थे, तो एक बार फिर उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद दोबारा फिर पुलिस में मामला दर्ज करवाकर मेडिकल करवाया गया।

जयपुर कांग्रेस के लिए बनाई गईं पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश की विधायक और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा (मोना तिवारी) आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने पहुंचीं थीं। इस दौरान किसी ने "भारत माता की जय" का नारा लगाया तो विधायक आराधना मिश्रा नाराज हो गईं और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि, अगर कोई नारा लगाना है तो वह कांग्रेस पार्टी की जय का नारा लगाओ। इसके अलावा कोई भी नारा लगाया जाएगा तो उसे अनुशासनहीनता मानी जाएगी।

बताया जा रहा है कि, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुस्तफ़ा और अफजल के बीच विवाद हुआ था। कार्यकर्ता मो. अफजल ने आरोप लगाया था कि भाजपा में रह चुके व्यक्ति को ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है।

'एडिटर्स गिल्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दबा रही थी उसे सामने लाया जा सके। राज्य सरकार की यह कार्यवाही मीडिया को धमकाने के सक्षम है वो भी देश की सर्वोच्च मीडिया संस्था को। पी.सी. आई. ने कहा इस समय हिंसाग्रस्त मणिपुर पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके ऐसे कदम हालात बिगाड़ सकते है। उन्होंने आरोप लगाया कि एफ. आई.आर. के. पत्रकारों पर इन्फॉर्मेशन एण्ड टैक्नॉलजी एक्ट की धारा 66 भी लगाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर चुका है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव का मुद्दा उछालने की "टाइमिंग"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमेटी की संरचना बताती है कि इस का गठन पूर्व निर्धारित एजेंडा के साथ किया गया है, मुद्दे के वास्तविक परीक्षण के लिये नहीं। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी. कश्यप जो कमेटी के सदस्य बनाये गये है, एक साथ चुनाव कराये जाने के विचार के प्रबल समर्थक रहे हैं।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कमेटी में विपक्ष के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है तथा इसे एक "धोखा" बताया है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में, उन्होंने कहा है कि वे उस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते, जिसकी "टर्म्स ऑफ रेफरेंस" इसके निष्कर्षों की गारंटी देने वाले तरीके से तैयार की गई हैं।

सरकारी अधिसूचना की "टर्म्स ऑफ रैफरैंस" की भूमिका में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा "राष्ट्र हित" में है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कमेटी इसे प्राप्त करने के उपायों/तरीकों का "परीक्षण एवं अभिशंसा" करेगी।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रधानमंत्री मोदी तथ उसके विचारधारा स्त्रोत" राष्ट्रीय स्वयं सेवक का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। मोदी कई सालों से इसकी बात करते आ रहे है, इसलिये इस मुद्दे को उठाने का समय सरकार के इरादों को संदिग्ध बना रहा है। यह स्पष्ट है कि अगले लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे क्योंकि इसके लिये संवैधानिक संशोधन तथा कानून बनाया जाना जरूरी होगा।

इस विचार को प्रस्तावित करने वालों, जिनमें प्रमुखत: भाजपा तथा आर.एस.एस. शामिल हैं, द्वारा दिये गये मुख्य तर्कों में से एक तर्क कहता है कि वर्तमान व्यवस्था किसी सरकार को शासन/प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करने का समय नहीं मिल पाता। इसके साथ ही, इस विचार के प्रस्तावकों एवं समर्थकों का कहना है कि पूरे साल चुनाव होते रहने के पैसे की बहुत बरबादी होती है।

ये दोनों दलीलें अर्थहीन है क्योंकि लोकतंत्र के संचालन में जनता की इच्छा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिये महत्वपूर्ण यह है कि जो सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी होती है, नया जनादेश पाने के लिये सत्ता त्याग देती है। जनता सरकार का चुनाव शासन करने के लिये करती है तथा निर्वाचित सरकार का यह दायित्व है कि वह पूरी क्षमता से करे तथा बहाने नहीं बनाये। इसके अलावा, विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव कराने लॉजिस्टिक की व्यवस्था इतनी बडी तथा जटिल हो जायेगी कि अगले साल मार्च-अप्रैल इसे इसली जामा पहनाना संभव नहीं हो पायेगा। संक्षेप में, यह प्रस्ताव मूल रूप से लोगों का ध्यान उनके अस्तित्व के लिये जरूरी चीजों से जुड़े मुद्दों से भटकाने के लिये रखा जा रहा है। ये मुद्दे हैं- महँगाई, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, बेरोज़गारी, दैनिक जरूरतें, महिला सुरक्षा तथा ऐसे ही अन्य अनेक मुद्दे। यह प्रस्ताव लोगों को यह सपने दिखाने तथा उन्हें आश्वस्त करने के लिये रखा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

16-17...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बैठक के बाद हैदराबाद के पास कांग्रेस की एक विशाल रैली होंगी, जिसमें तेलंगाना के लिए "पांच गारंटियाँ" घोषित की जाएंगी।

कांग्रेस अध्यक्ष एक यात्रा को भी रवाना करेंगे, जिसमें सी.डब्ल्यु.सी. सदस्य, पी.सी.सी. अध्यक्ष और सी.एल.पी. नेता शामिल होंगे। जो तेलंगाना की सभी 119 सीटों का दौरा करेंगे।

18 सितम्बर को कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रचार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के पहले नेता सामुदायिक भोज में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के पहले नेता सामुदायिक भोज में शामिल होंगे।

वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसुदन मिस्त्री प्रदेश सरकार व पदाधिकारियों से असंतुष्ट नज़र आए

मिस्त्री ने 25 लोकसभा सीटों के कई पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट अस्वीकार की और कहा, सिर्फ माला पहन कर नहीं आना है, आपको क्षेत्र में जाकर सच्चाई का पता लगाना है

- **कुछ पर्यवेक्षकों ने बताया कि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि, पार्टी के प्रदेश प्रमुख डोटासरा का व्यवहार बेहद रूखा है।**
- **कुछ पर्यवेक्षकों ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में कांग्रेसजनों की भागीदारी का कोई रोडमैप नहीं है।**

जयपुर, 4 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री लोकसभावार लगाए गए 25 पर्यवेक्षकों के काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही, सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी नहीं होने पर पर्यवेक्षकों की ओर से सवाल उठाए गए हैं।

राजस्थान में लोकसभावार लगाए गए 25 पर्यवेक्षकों की बैठक के दौरान जब पर्यवेक्षकों ने यह कहा कि, वे लोकसभा क्षेत्र में जाकर आए हैं, तो, कथित रुप से, मधुसूदन मिस्त्री ने उनकी रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि, आपको सिर्फ क्षेत्र में जाकर माला पहनकर नहीं आनी थी, बल्कि आपको क्षेत्र में वास्तविक स्थिति क्या है, योजनाओं को लेकर लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस कैसे जीत सकती है, इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन आप लोग सिर्फ क्षेत्र में जाकर अपना स्वागत कराने के साथ औपचारिकता निभाकर आए हैं। अब आप लोग फिर क्षेत्र में जाएं और पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके दें।

बताया जाता है कि, कई पर्यवेक्षकों ने यह भी जानकारी दी है कि, बहुत सारे जिलों और लोकसभा क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें कांग्रेसजनों की ओर से मिली हैं कि, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आम कांग्रेसजनों के साथ व्यवहार काफी रूखा है और इस बात की नाराजगी कांग्रेसजनों में नजर आ रही है। सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं को लेकर भी यह फीडबैक सामने आया है कि, सरकार ने योजनाएं तो एक के बाद एक शुरू कर दीं, लेकिन इन योजनाओं में कांग्रेसजनों की भागीदारी का कोई रोडमैप तैयार नहीं किया। कई पर्यवेक्षकों का कहना था कि, सरकार की मोबाइल फोन बांटने वाली जो योजना है, उसमें भी कांग्रेसजन किसी तरह की भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। बल्कि इसका फायदा उठाकर क्षेत्र में आर.एस.एस. और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने फोन बांटने वाली योजना को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है।

उल्लेखनीय कि, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें कि मोबाइल फोन राजस्थान सरकार बांट रही है, लेकिन जब लोगों से बात की जा रही है, तो वह वोट मोदी को देने की बात कर रहे हैं।

पर्यवेक्षकों की ओर से दी गई इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि, यदि इतनी बड़ी योजनाओं का लाभ कांग्रेस को नहीं मिलकर भाजपा को मिलता दिख रहा है, तो योजनाएं बनाने के साथ ही ऐसा रोडमैप बनाना चाहिए था, जिसमें कांग्रेसजन सीधी भागीदारी निभाते, ताकि चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल पाता।

बैठक में चर्चा के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने सभी पर्यवेक्षकों से कहा है कि, वे फिर क्षेत्र में जाएं और वास्तविक स्थिति का पता लगाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। ताकि चुनाव से पहले हकीकत सामने आ सके।

कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति गठित

नयी दिल्ली, 04 सितंबर। कांग्रेस ने 16 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को शामिल किया गया है।

कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, खड़गे ने पार्टी में हुए चुनाव के बाद इस समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि, समिति में खड़गे,

- **समिति में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के अलावा 13 अन्य नेता शामिल हैं।**

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टी. एस. सिंहदेव, के. जे.जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अम्मी याज्जनिक, पीएल पुनिया, ओमकार मरकाम तथा के. सी. वेणुगोपाल को शामिल किया गया है।

'छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के आदेश को क्यों ना रद्द कर दिया जाए'

राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एवं रजिस्ट्रार को जवाब तलब किया

- **राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने 12 अगस्त को राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं कराने के निर्णय की घोषणा की थी।**

जयपुर, 4 सितंबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर पूछा है कि, इस साल छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के संबंध में गत 12 अगस्त को जारी आदेश को क्यों न रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश विकाश घोसल्या की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि, राज्य सरकार ने गत 12 अगस्त को एक प्रशासनिक आदेश जारी कर इस साल प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया।

याचिका में कहा गया कि, विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है और इसके संबंध में राज्य सरकार कोई भी निर्णय लेकर दखल नहीं दे सकती है। विश्वविद्यालय भी सिंडिकेट बैठक में निर्णय लेकर ही आगे की कार्रवाई कर सकता है।

ऐसे में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का राज्य सरकार का निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि, छात्र का मूलभूत अधिकार है कि वह छात्रसंघ में निर्वाचित हो और उसके लिए मतदान करे। केरल वि.वि. बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में व्यवस्था दे चुका है।

याचिका में यह भी कहा गया कि, संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि, कोई भी कानून यदि मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है तो ऐसे कानूनों को शून्य माना जाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश के जरिए विद्यार्थियों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया। जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, राज्य सरकार ने पूर्व में ही केविएट दायर कर दी थी और उन्हें याचिका की कॉपी भी दी जा चुकी है, ऐसे में जवाब पेश करने के लिए इतना अधिक समय नहीं दिया जा सकता। इस पर अदालत ने राज्य सरकार और विवि प्रशासन को जवाब पेश करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है।

दो महिला नेताओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर थीं, की छवि उनके द्वारा उठाये गये कई गलत कदमों के साथ ही, उनके खराब स्वास्थ्य के कारण काफी नीचे पहुंच गई है। पार्टी के तत्कालीन महारथी एल.के. अडवाणी के साथ अपने मतभेदों को सार्वजनिक कर दिये जाने के बाद, तथा इस मांग के लिये एक लम्बा अभियान चलाने के बाद कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जगह, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिये, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी तथा अपना नया दल बनाना पड़ा, जिसकी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं रही। 2011 में, भाजपा में उनकी वापसी के बाद, पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का रास्ता दिखा दिया, जहां वे विधायक चुन ली गईं। 2018 में, उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के आधार पर राजनीति से सन्यास ले लिया, लेकिन पिछले साल उस समय वे फिर से सक्रिय हो गईं, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में मद्यनिषेध की मांग करते हुए एक आंदोलन चलाया।

इसलिये उनके वर्तमान स्वर को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्वयं को फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश मात्र के रूप में ही देखा जा सकता है। यह एक अलग बात है कि चूंकि भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई गुट बंदी से ग्रस्त है, इसलिये उमा भारती भगवा पार्टी की परेशानियों को बढ़ा जरूर सकती है। वहीं दूसरी तरफ, वसुंधरा राजे, पार्टी हाई कमान द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने के बावजूद, आज भी एक प्रासंगिक राजनैतिक हस्ती बनी हुई हैं।

मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समय यह संभव नहीं था।

रिपोर्ट में कहा गया है, "इंटरनेट बैन ने हालात और बिगाड़ दिए। सरकार द्वारा संचार माध्यमों को ठप्प करने का पत्रकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इससे पत्रकारों की ममता को आपस में, संपादक से और सूत्रों से संवाद करने में परेशानी हुई। इससे मीडिया पर यह भी प्रभाव पड़ा कि बिना संपर्क व्यवस्था के एकत्रित किए गए स्थानीय समाचारों में स्थिति का एक संतुलित चित्र नहीं दिया जा सका।"

रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट बंद होने, संचार और परिवहन के साधन अस्त-व्यस्त होने के कारण मीडिया को पूरी तरह राज्य सरकार के वक्तव्य पर ही निर्भर रहना पड़ा। ई.जी.आई. ने कहा कि राज्य नेतृत्व के सदस्यों ने कुकी आदिवासियों के कुछ वर्गों को अवैध घुसपैठिये और विदेशी कहा वो भी बिना किसी विश्वसनीय जानकारी या प्रमाण के।

रिपोर्ट के अनुसार, "यह इस तथ्य के बावजूद है कि 1901 से 2011 हर दशक में होने वाली जनगणना में गैर-नागा आदिवासी जनसंख्या में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई।" दरअसल म्यांमार में जो सैन्य विद्रोह हुए उससे मिज़ोरम में 40,000 और मणिपुर में 4000 शरणार्थी आए बताए जिसका उपयोग सभी कुकी इसी को आधार बनाकर कुकी आदिवासियों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। "इसे संसाधनों पर दबाव के रूप में प्रस्तुत किया गया था और साथ ही राजनैतिक स्थान के लिए लड़ाई के रूप में भी और राजनेता अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बाहरी लोगों का डर दिखा रहे थे।" एडीटर्स गिल्ड के सदस्यों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं जिनमें शामिल हैं 153-ए (दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना), 200 (झूठी घोषणा का सच्ची बताकर उपयोग करना), 208 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाना) तथा आई.टी. एक्ट और प्रेस काउंसिल एक्ट की कई धाराएं।

सिंह ने कहा, "मैंने एडीटर्स गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी दी है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो स्थल पर आइए, ज़मीनी हकीकत देखिए, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलिए, सभी पीड़ितों से मिलिए और जो आपको पता चले वह प्रकाशित कीजिए। वरना केवल कुछ लोगों से मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना लोगों के लिए लाभदायी नहीं है और भर्त्सना के योग्य है। यह कहना है कि केवल एक ही समुदाय को निकाला गया, गलत है क्योंकि यह कार्रवाई 2015 में आरंभ हुई और आम जनता के कल्याण के लिए 413 घर खाली करवाए गए है। इनमें से 59 कुकी के, 143 मैइती के, 137 मणिपुर मुसलमानों के, 38 नागाओं के और 36 नेपालियों के हैं।"

मुख्यमंत्री ने अचरज जताया कि किसी ने उस मां का उल्लेख नहीं किया जिसने निर्वस्त्र घुमाई गई महिलाओं को कपड़े दिए और उन्हें घर भेजा। उन्होंने कहा कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाओं पर कोई नहीं बोल रहा है।

सिंह ने कहा कि राज्य में चिन्हित अवैध घुसपैठियों का बायोमीट्रिक विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, "केन्द्र ने हमें यह प्रक्रिया सितम्बर तक पूरी करने को कहा है लेकिन हमने एक साल का विस्तार मांगा है क्योंकि हमें और गांव ढूंढने है।"

उनको शिकायत थी कि ई.जी.आई. की रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार द्वारा गठित कई कमेटियां घटना की जाँच कर रही है।

सिंह ने कहा कि एक एफ.आई.आर. कुकी इन्पी मणिपुर नेता के. हाओकिप के विरूद्ध दर्ज की गई है, उन्होंने कहा कि कोई मैईती भारत-म्यांमार सीमा के मोरेह गांव में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक राजनैतिक समाधान नहीं हो जाता।

ऑल वर्किंग मणिपुर जर्नलिस्ट्स यूनियन और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ने भी सुनी सुनाई बातों पर आरोप लगाने के लिए ई.जी.आई. की आलोचना की है। 3 मई को मणिपुर दंगे आरंभ होने के बाद 160 जानें जा चुकी हैं और सैंकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। मैइती मणिपुर की जनसंख्या का 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी कुकी और नागा 40 प्रतिशत हैं जो पहाड़ों में रहते हैं।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908